रविवार, 22 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08



एडिलेड में भारत की ऐतिहासिक जीत

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

47 साल साथ दिखेंगे रजनीकांत और कमल हसन

Page-05



सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा फैसला,

रेट के टैरिफ पर रोक

- **टैरिफ अवैध करार, आयात-निर्यात कंपनियों को राहत**
- **डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति को झटका**



अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ फैसलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने शांति के समय में 50 साल पुराने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके टैरिफ नहीं लगा सकते. यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया. इससे ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ अवैध हो गए. कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसमें सभी देशों से आने वाले आयात पर 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है. यह टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और 150 दिनों तक चलेगा. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वे सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा रहे हैं, जो लगभग तुरंत प्रभावी होगा. उन्होंने सेक्शन 122 कानून का सहारा लिया, जो राष्ट्रपति को अस्थायी रूप से 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है.

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक अंतरिम ट्रेड डील हुई थी. इसमें भारत पर 50 प्रतिशत तक के पेनल्टी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था. कोर्ट के फैसले से 18 प्रतिशत टैरिफ का कानूनी आधार खत्म हो गया. इससे भारत पर टैरिफ पुराने स्तर यानी 3.5 प्रतिशत (मोस्ट फेवर्ड नेशन दर) पर आ सकता था. लेकिन नए 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ के साथ अब भारत पर कुल टैरिफ लगभग 13.5 प्रतिशत हो सकता है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत पर अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा. इससे भारतीय निर्यात जैसे कपड़ा, दवा और रत्न आदि पर असर पड़ सकता है.

भारत सरकार ने इस पर पहली प्रतिक्रिया दी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, 'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं.' मंत्रालय ने शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया. बयान में कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन की ओर से कुछ कदमों की घोषणा हुई है. सरकार इन सभी घटनाक्रमों और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है. इससे भारत-अमेरिका व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, यह देखा जा रहा है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ीं मुश्किलें

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप



उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बलात्कार एवं यौन शोषण विरोधी विशेष न्यायालय के सहायक न्यायाधीश ने पुलिस को ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरासिया ने पहले की पुलिस निष्क्रियता को खारिज करते हुए झोआंसी पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस फैसले से उस विवाद में और भी तीव्रता आ गई है जो माघ मेले के दौरान इन आरोपों के सामने आने के बाद से इस क्षेत्र में व्याप्त है। यह मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत 28 जनवरी को दायर याचिका से शुरू हुआ। ब्रह्मचारी ने स्वामी के आश्रम पर बच्चों के सुनियोजित यौन शोषण का आरोप लगाया और दावा किया कि वाराणसी के विद्यामठ में 'गुरु सेवा' की आड़ में नाबालिगों को जबरन यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने सबूत के तौर पर एक सीडी प्रस्तुत की और लगभग 20 पीड़ित बच्चों का जिक्र किया, जिन्होंने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने धार्मिक आड़ में छिपे शोषण के एक पैटर्न को उजागर किया। 13 फरवरी को अदालत ने दो नाबालिग पीड़ितों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए बयान दर्ज किए, जिनके आधार पर आदेश जारी किया गया। पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर न्यायाधीश ने इन बयानों की समीक्षा करने के बाद एफआईआर जारी करने से पहले फैसला सुरक्षित रख लिया। इस प्रक्रियात्मक सख्ती से पीओसीएसओ के तहत बाल संरक्षण कानूनों को प्राथमिकता मिलती है, जो पुलिस की धीमी कार्रवाई के बीच एक चर्चित धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ दुर्लभ न्यायिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। ▸▸

'नेकी कर कुएं में डाल...'

का संदेश, चुनावी माहौल में नई चर्चा



मेरठ के कार्यक्रम में भागवत ने कार्यकर्ताओं को पांच मंत्र दिया. जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके पांचवें मंत्र की हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसे पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें. अक्सर चुनावों के वक्त नेताओं में टिकट और सीटों की होड़ मच जाती है, लेकिन भागवत ने कहा कि "काम ऐसा करो कि उसमें टिकट या सीट की कोई मांग न हो. नेकी करो और कुएं में डालो." उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति संघ का नाम तक नहीं जानता, लेकिन देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो संघ उसे अपना ही सदस्य मानेगा. उनका सीधा संदेश था कि काम 'एक्सीलेंस' के साथ होना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ के लिए. मेरठ और लखनऊ के बाद अब मोहन भागवत का अगला पड़ाव उत्तराखंड है. 22 और 23 फरवरी को वे दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे. बता दें कि संघ अपने स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 'शताब्दी वर्ष' मना रहा है. इसके तहत उत्तराखंड में बड़े स्तर पर हिंदू सम्मेलनों की तैयारी है. संघ ने पूरे प्रदेश में 1,000 हिंदू सम्मेलन करने का बड़ा लक्ष्य रखा है, ताकि जमीन स्तर पर लोगों को जोड़ा जा सके.

'ऑपरेशन सिंदूर' पर सियासी संग्राम तेज

अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 11 विमान गिरने का दावा



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 11 जेट विमान गिरने का दावा किया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है. सरकार को अपना पक्ष साफ़ करना चाहिए.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को टैग करते हुए भाजपा पर हमला किया. उन्होंने पूछा कि ये हमारे देश के सम्मान का मामला है. सरकार को इस पर अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था? अमेरिकी ट्रेड डील की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि क्या डील ने मुँह पर सील लगा दी है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "क्या DEAL ने मुंह पर SEAL लगा दी है? या तो बात साफ की जाए कि क्या हुआ था या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को ख़ारिज किया जाए. भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है."?

ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड में बनेगी फिल्म



विवेक अग्निहोत्री अब एक ऐसे सैन्य मिशन को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे. हालांकि, विवेक हमेशा की तरह सस्पेंस बनाए रखने में माहिर हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर कहानी क्या है. "मैं फिलहाल किसी खास फिल्म का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हां, मैं एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं. यह मेरे दिल के बहुत करीब है और सही वक्त आने पर मैं खुद इसका ऐलान करूंगा."

'पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति...',

CRPF के स्थापना दिवस पर आयोजित परेड में क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित CRPF(Central Reserve Police Force) के 87वें स्थापना दिवस पर आयोजित परेड को संबोधित करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के योगदान की जमकर सराहना की. उन्होंने CRPF के 2200 से अधिक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की शांति और एकता बनाए रखने में बलिदान देने वाले जवानों का योगदान अविस्मरणीय है. इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 11-12 वर्ष पहले देश के कुछ क्षेत्र (पूर्वोत्तर, नक्सल प्रभावित इलाके और जम्मू-कश्मीर)लगातार हिंसा की चपेट में रहते थे. उस समय बम धमाकों और गोलीबारी की घटनाएं आम थीं, लेकिन आज इन क्षेत्रों में स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण है. अमित शाह ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल की समस्या को पूरी तरह मुक्त कर देगी. इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक समय देश के 12 राज्यों और अनेक जिलों में माओवाद का गहरा प्रभाव था, लेकिन सरकार के ठोस संकल्प और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से स्थिति तेजी से बदली है.



आगे उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण समस्या को कुछ वर्षों के भीतर नियंत्रित करना सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है. गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक बदलावों (अनुच्छेद 370 हटाना) के बाद भी बड़े पैमाने पर अशांति नहीं हुई और एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसमें सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही.



प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का किया स्वागत

द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। लूला ने एपेक्स कार्यालय का उद्घाटन किया और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।



टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने हैदराबाद हाउस में भी द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। इस बैठक में आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, कृषि, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। इस स्वागत समारोह में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बल भी मौजूद थे।राष्ट्रपति लूला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लूला ने नई दिल्ली में ब्राजील व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसी (एपेक्स) का पहला कार्यालय भी उद्घाटित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस कदम से ब्राजील के उत्पादों और सेवाओं को विदेशों में बढ़ावा मिलेगा और ब्राजील की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित होगा।भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रेगा ने बताया कि राष्ट्रपति लूला अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं। इसमें 11 से अधिक कैबिनेट मंत्री, 300 से अधिक व्यवसायी और 50 प्रमुख सीईओ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और लूला के बीच उत्कृष्ट केमिस्ट्री है और दोनों नेता न केवल सहकर्मी बल्कि गहरे मित्र बन चुके हैं।राष्ट्रपति लूला की यह भारत यात्रा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रासीलिया यात्रा के बाद हो रही है। ब्रासीलिया यात्रा 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लूला अपने साथ ब्राजील की शीर्ष कंपनियों के सीईओ का बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं। ये सीईओ विभिन्न बिजनेस फोरम में भाग लेकर भारत और ब्राजील के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे।राजदूत के अनुसार, यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक रूप से एक नए स्तर पर ले जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सतत विकास, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी है।इस यात्रा से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत और ब्राजील के संबंध अब नए आयाम पर पहुँच रहे हैं और भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग और भी मजबूत होगा। इस पहल से व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, जो दोनों देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक सहयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इज़राइल की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा की पूर्व संध्या पर, भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को और गहरा और विस्तारित करने की तैयारियां तेज हैं। दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित बैलिस्टिक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली, लेजर हथियार, लंबी दूरी की स्टैंड-ऑफ मिसाइलें और ड्रोन के संयुक्त विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।सूत्रों के अनुसार, इज़राइल ने भारत के साथ नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों को साझा करने पर सहमति दी है, जिनमें हाई-टेक लेजर रक्षा प्रणाली और अन्य स्टैंड-ऑफ सिस्टम शामिल हैं। ये तकनीकें इज़राइल ने अब तक किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की थीं। इस विस्तारित रक्षा सहयोग की नींव रक्षा सचिव आर.के. सिंह की पिछले नवंबर में इज़राइल यात्रा के दौरान रखी गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।भारत इज़राइल के साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन का मुख्य आधार है। यह प्रणाली भारतीय आंतरिक क्षेत्रों को दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।इज़राइल की एरो, डेविड्स स्लिंग और आयरन डोम प्रणालियों का अनुभव भारत के लिए मार्गदर्शक होगा। पिछले जून में तेल अवीव ने ईरान द्वारा दागी गई 98 प्रतिशत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर अपनी प्रणाली की दक्षता साबित की थी।



PM किसान योजना:

22वीं किस्त फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना

श्रीनगर में CRPF वाहन नहर में गिरा 9 जवान घायल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

श्रीनगर में शनिवार को एक गंभीर हादसा हुआ, जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक बंकर वाहन सड़क से फिसलकर सौरा के दागपोरा इलाके में नहर में जा गिरा। इस घटना में कम से कम नौ जवान घायल हो गए। हादसा अहमद नगर के दगपोरा रोड पर उमर हेयर के पास हुआ, जब वाहन चालक कथित तौर पर वाहन पर नियंत्रण खो बैठा।सीआरपीएफ की 21वीं बटालियन के सात घायल जवानों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में दो अन्य घायल जवानों को इलाज के लिए शेर-ए-कश्मीर आयुर्वेद संस्थान (एसकेआईएमएस), सौरा ले जाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी घायल जवानों की हालत स्थिर है और उनका उपचार जारी है। उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं, लेकिन किसी की स्थिति गंभीर नहीं बताई जा रही।जवानों की पहचान नागिंदर सिंह (36), अजीत कुमार राम (36), राज किशोर राय (40), अमित कुमार यादव (38), राजधन राम (55), मानकर कुमार (40) और नीरज कुमार (45) के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा दल लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है और सभी घायल जवानों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर सुरक्षा बल और मेडिकल टीम तैनात कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालक ने सड़क पर वाहन का नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वाहन सीधे नहर में गिर गया। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और सड़क सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाए हैं।अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी घायल जवानों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सीआरपीएफ और स्थानीय प्रशासन सतर्कता बढ़ा चुके हैं।



अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद

भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटकर 10%

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक शुल्कों को रद्द किए जाने के बाद भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत के फैसले और अमेरिका की ओर से 10 प्रतिशत के अस्थायी आयात शुल्क संबंधी नए आदेश के बाद 24 फरवरी से भारतीय वस्तुओं पर केवल 10 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लागू होगा, जिससे पहले की तुलना में बोझ काफी कम हो जाएगा। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक शुल्क कानून के दायरे से बाहर थे। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा। इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद 20 फरवरी को जारी घोषणा में ट्रंप ने कहा कि 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात शुल्क लगाया जाएगा।गौरतलब है कि अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया था। इसके बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया गया, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि नए आदेश के बाद भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा।यह शुल्क अमेरिका में लागू सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) आयात शुल्क के अतिरिक्त होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उत्पाद पर पांच प्रतिशत एमएफएन शुल्क है तो कुल प्रभावी शुल्क 15 प्रतिशत हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए।विश्लेषकों के अनुसार, संशोधित व्यवस्था के तहत पारस्परिक शुल्क अब भारत के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 55 प्रतिशत हिस्से पर लागू होगा, जबकि करीब 40 प्रतिशत वस्तुएं छूट श्रेणी में रहेंगी। हालांकि इस्पात, एल्युमिनियम और तांबे पर 50 प्रतिशत तथा वाहनों के कुछ कलपुर्जों पर 25 प्रतिशत का क्षेत्रीय शुल्क जारी रहेगा।ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पूर्व सहमति के अनुरूप जारी रहेगा।

दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट:

लाल किला और चांदनी चौक निशाने पर, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी खतरे की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। इन सूचनाओं के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी राजधानी, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इंटेलिजेंस नोट के अनुसार, आतंकियों की नजर लाल किला के आसपास के क्षेत्रों और घनी आबादी वाले चांदनी चौक में स्थित मंदिरों पर है। आशंका है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए हमला करने की कोशिश की जा सकती है। यह साजिश 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद कथित बदले की कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है। एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि देशभर के प्रमुख मंदिर संभावित निशाने पर हो सकते हैं। सुरक्षा इनपुट के बाद संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।



अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, वाहनों की सघन जांच की जा रही है और धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों के आसपास एंटी-सैबोटाज जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह अलर्ट 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के करीब तीन महीने बाद आया है। उस हमले में विस्फोटकों से लदी एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटकों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई थी। जांच एजेंसियों ने कार चालक की पहचान उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के रूप में की थी, जो फरीदाबाद से जुड़ा था। डीएनए विश्लेषण से उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई और उसे हरियाणा में सक्रिय एक बड़े आतंकी मॉड्यूल से जोड़ा गया। इससे पहले एजेंसियों ने फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर मॉड्यूल के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

संपादक की कलम से

बांग्लादेश में चुनाव हर बार देश की राजनीतिक दिशा और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का आईना साबित होते हैं। आगामी चुनाव भी कोई अपवाद नहीं है। इस बार की लड़ाई केवल सत्ता पर कब्ज़ा करने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों, सार्वजनिक भरोसे और विकास की दिशा को तय करने की है।पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई प्रगति की है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, विभाजन और विरोधी दलों के बीच टकराव ने अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दी है। ऐसे में चुनाव केवल मतदाताओं के अधिकार का उपयोग नहीं, बल्कि उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी का परीक्षण भी है।लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि जनता अपनी आवाज़ के माध्यम से शासन का मार्गदर्शन करती है। इसलिए, हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच-समझकर करना चाहिए। चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए; यह उम्मीदवारों की योग्यता, उनके एजेंडा, विकास योजनाओं और न्यायप्रियता का मूल्यांकन करने का अवसर भी है।इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। हिंसा, भय और धमकियों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। साथ ही, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में सहायक होते हैं।बांग्लादेश का भविष्य उसकी जनता के हाथों में है। यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का अवसर है, बल्कि यह तय करने का भी समय है कि लोकतंत्र के मूल्यों, विकास और सामाजिक न्याय को किस दिशा में ले जाना है।इसलिए, हर नागरिक को मतदान में भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतंत्र की यह प्रक्रिया सही मायनों में सफल और पारदर्शी हो। चुनाव का परिणाम केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्र की दिशा तय करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

बंगाल में मतदाता सूची की निगरानी अब न्यायिक अधिकारियों के हाथ

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के टकराव को देखते हुए मतदाता सूची की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी। यह फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है।



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच जिस तरह का टकराव और अविश्वास का माहौल बना है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने पूरी प्रक्रिया को न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में कराने का निर्देश दिया है।यह आदेश ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। अदालत ने कहा कि अब मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में होगा, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान में कार्यरत जिला जज और अतिरिक्त जिला जज स्तर के बेदाग रिकॉर्ड वाले न्यायिक अधिकारियों को इस कार्य के लिए उपलब्ध कराएं। ये अधिकारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के कार्यों का निर्वहन करेंगे और लंबित दावों की समीक्षा करेंगे। विवाद का मूल प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को ईआरओ के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीएम रैंक (ग्रुप-बी) के अधिकारियों को उपलब्ध कराया है या नहीं। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि आवश्यक ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि ऐसे एसडीएम रैंक के अधिकारी, जो अर्द्ध-न्यायिक आदेश पारित कर सकें, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं कराए गए। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर और विशेष रोल ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को आदेश पारित करने से रोके जाने के बाद आयोग ने "स्पेशल रोल ऑब्जर्वर" की नई श्रेणी नियुक्त कर दी, जो ईआरओ द्वारा पारित आदेशों की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये अधिकारी ईआरओ के निर्णयों को सामूहिक रूप से अस्वीकार नहीं कर सकते और न ही उन पर हावी हो सकते हैं।हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इन दावों का खंडन किया गया और कहा गया कि विशेष रोल ऑब्जर्वर शुरुआत से ही नियुक्त थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों संवैधानिक संस्थाओं—लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार और चुनाव आयोग—के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए न्यायिक निगरानी के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। अदालत के निर्देश के अनुसार अब जिला जज या अतिरिक्त जिला जज स्तर के वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य लंबित दावों और आपत्तियों का निष्पक्ष और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना है।आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग पांच लाख नाम मतदाता सूची से खारिज किए जा चुके हैं, जबकि करीब पांच लाख लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। लगभग 55 लाख नाम विभिन्न स्तरों पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। कुल मिलाकर करीब 70 लाख नामों पर असर पड़ सकता है। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जानी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य की सियासत में दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। अब मतदाता सूची से जुड़ी पूरी प्रक्रिया न्यायपालिका की निगरानी में होगी, जिससे चुनावी पारदर्शिता पर विशेष जोर रहेगा। ऐसे में आने वाले चुनावों से पहले यह आदेश पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।

राहुल गांधी भिवंडी अदालत में पेश, आरएसएस मानहानि मामले की सुनवाई मार्च में



टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

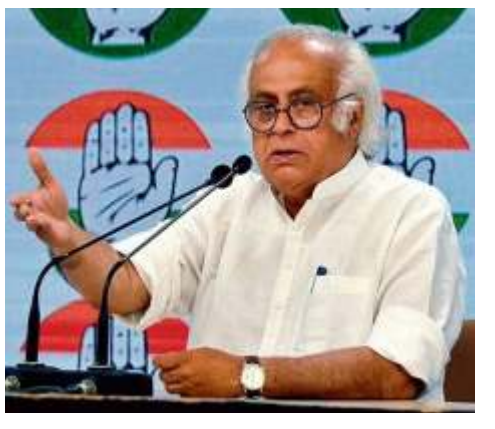
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को 2014 के आरएसएस मानहानि मामले में भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पेश हुए। यह मामला भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर किया गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल, जो मूल जमानती थे, के निधन के बाद नए जमानती पेश करना आवश्यक हो गया। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल अदालत में मौजूद थे। अय्यर ने कहा कि यह मानहानि का मामला है और उन्होंने न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मामले को आगे बढ़ाने और जनता के सामने सत्य पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अय्यर ने पत्रकारों से कहा, "भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में हमारे जमानतदार शिवराज पाटिल का निधन हो गया, जिसके कारण हमें नए जमानतदार की आवश्यकता पड़ी। राहुल गांधी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी आज अदालत में उपस्थित थे। हमें विश्वास है कि इस मामले की सच्चाई सामने आएगी और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है।"उन्होंने यह भी कहा कि उचित समय पर सभी सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में निर्धारित की है।महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राहुल गांधी सांसद और कांग्रेस के नेता हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस चेहरे को उजागर किया है, जिसे वे असली चेहरा मानते हैं।इस पेशी के साथ ही कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और सत्य को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सियासी घमासान,

कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा हमला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर देश की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता देशहितों से समझौता है और प्रधानमंत्री की "छवि बचाने" की जल्दबाजी के कारण भारत को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि दो फरवरी 2026 की रात भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रंप की शुल्क नीति को खारिज किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके "अच्छे मित्र" हैं और व्यापार समझौता जारी रहेगा।रमेश ने दावा किया कि 10 मई 2025 को ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर 'ऑपरेशन सिंदूर' रुकवाया था। उन्होंने यह भी कहा कि दो फरवरी को ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है और यह प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर हुआ। कांग्रेस नेता ने प्रश्न उठाया कि लोकसभा में उस दिन ऐसा क्या हुआ, जिससे प्रधानमंत्री को तत्काल 'व्हाइट हाउस' से संपर्क करना पड़ा।उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन और प्रतीक्षा की होती तो भारतीय किसान इस संकट से बच सकते थे और देश की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती। उनके अनुसार यह समझौता प्रधानमंत्री की "व्यग्रता और आत्मसमर्पण" का परिणाम है।उधर, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक शुल्क को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार कर लगाने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समझौता जारी रहेगा और इसे "एक अलग तरीके से" लागू किया जाएगा।इस बीच, अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटाने का कार्यकारी आदेश भी जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।





UGC ने भारत में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की, छात्रों को चेतावनी

देशभर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पूरे भारत में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है और छात्रों को इनमें प्रवेश न लेने की चेतावनी दी है। आयोग ने बताया कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली में पाई गई है।UGC के अनुसार, ये फर्जी संस्थान बिना मान्यता के डिग्री प्रदान करते हैं, जिन्हें नौकरी, आगे की पढ़ाई या सरकारी सेवाओं में मान्यता नहीं दी जाती। पिछले दो साल में ऐसे संस्थानों की संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में खतरनाक स्थिति बन रही है। आयोग ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता U G C की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें।विशेषज्ञों का कहना है कि फर्जी विश्वविद्यालय छात्रों को आकर्षित करने के लिए कम फीस, जल्दी डिग्री और आसान पढ़ाई का लालच देते हैं। इनमें सही शिक्षक, उचित सुविधाएं या शिक्षा का स्तर



नहीं होता। कुछ संस्थान छात्रों को भ्रमित करने के लिए खुद को विदेशी विश्वविद्यालय के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, ताकि छात्रों को फंसा सकें।UGC ने स्पष्ट किया कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों में प्राप्त डिग्री का कोई वैध अधिकार नहीं होता। ऐसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होते हैं और न ही उच्च शिक्षा या किसी अन्य शैक्षणिक अवसर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि जागरूकता ही छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है।आयोग ने कहा कि पिछले दो वर्षों में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे संस्थान अक्सर बिना सरकारी अनुमति और मान्यता के खुले रहते हैं और आर्थिक लाभ के लिए छात्रों का शोषण करते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके चलते छात्रों और उनके परिवारों का वित्तीय नुकसान होने के साथ ही भविष्य के शैक्षणिक और पेशेवर अवसर भी प्रभावित होते हैं।UGC ने चेतावनी दी है कि छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान का चुनाव करते समय उसकी मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षक और सुविधाओं की पूरी जानकारी लेना अनिवार्य है। इस चेतावनी से स्पष्ट हो गया है कि फर्जी विश्वविद्यालयों की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ प्रशासन और आयोग को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने और प्रवेश लेने से पहले संस्थानों की वैधता की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

वीनस विलियम्स को बीएनपी पारिबास ओपन में वाइल्ड कार्ड, इंडियन वेल्स में होगी वापसी



सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को अगले महीने दक्षिणी कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल और युगल ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है। यह 45 वर्षीय खिलाड़ी 2024 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। पिछली बार उन्हें भी वाइल्ड कार्ड मिला था, लेकिन वह पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थीं। वीनस विलियम्स तीन बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने 2001 में एक विवादित घटना के बाद 2002 से 2016 तक इस प्रतियोगिता का बहिष्कार किया था। टूर्नामेंट के निदेशक टॉमी हास ने शुक्रवार को कहा, ''इस वर्ष की प्रतियोगिता के लिए पहला वाइल्ड कार्ड वीनस विलियम्स को देना हमारे लिए सम्मान की बात है। वीनस इस खेल की दिग्गज खिलाड़ी हैं और हमारे खेल के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं।''बीएनपी पारिबास ओपन का आयोजन 4 मार्च से 15 मार्च तक किया जाएगा। वीनस ने इस अवसर पर कहा, ''मैं इंडियन वेल्स में वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हूं और कैलिफोर्निया में खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।''वीनस ने इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लिया था, लेकिन एकल और युगल दोनों में पहले दौर में बाहर हो गई थीं। उनके फैन्स को इंडियन वेल्स में उनके प्रदर्शन की उम्मीद है, जहां वह लंबे समय बाद वापसी कर रही हैं।टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड मिलने से वीनस को एक और मौका मिलेगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करें और अपने अनुभव का फायदा उठाकर मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करें। यह कदम बीएनपी पारिबास ओपन के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है, क्योंकि वीनस जैसी दिग्गज खिलाड़ी का खेलना टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाता है और दर्शकों को रोमांचक मुकाबलों का अनुभव देता है।



ऑस्ट्रेलिया की विदाई पर मार्श मायूस, कहा — हम बेहतर कर सकते थे

एडिलेड में भारत की ऐतिहासिक जीत



भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला एडिलेड ओवल मैदान पर खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराकर यादगार जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम का अपने घर पर लगातार 10 सीरीज जीतने का सिलसिला भी यहीं टूट गया।मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 177 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और नियमित अंतराल पर रन बटोरते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। मध्यक्रम की संयमित बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में तेज रन गति ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कड़ी टक्कर दी। विकेटों के लगातार गिरने से मेजबान टीम कभी भी मैच में पूरी तरह नियंत्रण हासिल नहीं कर सकी। निर्धारित 20 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम 159 रन तक ही पहुंच पाई और भारत ने मुकाबला 17 रनों से अपने नाम कर लिया।इस जीत के साथ भारतीय टीम ने जून में होने वाले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले मजबूत तैयारी का संकेत दिया है। खिलाड़ियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और विदेशी परिस्थितियों में मिली यह सफलता टीम के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसके घरेलू मैदान पर हराना भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ा कदम है। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ टीम की क्षमता साबित की है बल्कि आगामी विश्व कप के लिए प्रतिद्वंद्वी टीमों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत खिताब की दौड़ में गंभीर दावेदार बनकर उभरा है।

बीसीसीआई ने भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ को संरचित समर्थन देने की घोषणा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ (सीएबीआई) को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर समर्थन देने के लिए एक संरचित ढांचा लागू करने की घोषणा की। इस पहल के तहत दृष्टिबाधित क्रिकेट टीमों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, घरेलू श्रृंखलाओं में सहायता और स्टेडियम उपयोग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीमों ने पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुरूष टीम ने विश्व कप जीता है, वहीं महिला टीम ने पहला महिला विश्व कप अपने नाम किया। इन उपलब्धियों ने भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है।बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस अवसर पर कहा, ''भारत के दृष्टिबाधित क्रिकेटरों की उपलब्धियां क्रिकेट समुदाय के लिए गर्व का विषय हैं। इस संरचित समर्थन से हम इन खिलाड़ियों को बेहतर अवसर, बुनियादी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान कर सकेंगे। हमारा खेल का विजन समावेशिता पर केंद्रित है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सहयोग से टीमों को आत्मविश्वास मिलेगा और ये खिलाड़ी आने वाले क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे।''बीसीसीआई की इस पहल के तहत मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में मदद की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के अंतर्गत पुरुष और महिला टीमों को साल में दो बार विदेश में टूर्नामेंट खेलने के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता दी जाएगी। घरेलू श्रृंखला सहायता के तहत भारत में द्विपक्षीय श्रृंखला के दौरान मेजबान और विदेशी टीमों के ठहरने और अभ्यास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, स्टेडियमों का इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जाएगा, जहां बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त स्टेडियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध होंगे।

सुपर आठ से पहले सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के फॉर्म पर उठे सवालों को किया खारिज



टी20 विश्व कप में लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर आठ मैच से पहले सवाल उठे। इस पर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिंदास और आत्मविश्वास भरा जवाब दिया।सूर्यकुमार ने कहा, ''मैं उन लोगों को लेकर चिंतित हूं जो अभिषेक की फॉर्म की चिंता कर रहे हैं। उन्हें अभिषेक के फॉर्म की इतनी चिंता क्यों है।'' उन्होंने स्पष्ट किया, ''पिछले साल अभिषेक ने हम सभी को कवर किया और अब उसे कवर करना हमारी जिम्मेदारी है।''कप्तान ने अभिषेक की पिछले एक साल की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा, ''मैं उन टीमों के बारे में सोच रहा हूं जो उसके खिलाफ खेल रही हैं। जब वह रन बनाता है तो क्या होता है, यह हम सब जानते हैं। टीम खेल में यह होता रहता है।''अभिषेक को लगातार मैचों में ऑफ स्पिनर ने आउट किया है और वह स्लॉग शॉट खेलते समय विकेट गंवा बैठे हैं। इसके बावजूद सूर्यकुमार ने कहा कि वह इससे चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''टीम को अभिषेक से एक खास प्रकार के खेल की जरूरत है और वह यही कोशिश कर रहा है। हम नहीं चाहते कि वह अपनी पहचान खो दे। अगर यह तरीका काम नहीं करता तो उसे कवर करने के लिए हम हैं।''दक्षिण अफ्रीका के अभ्यास सत्र में कप्तान एडेन मार्कराम दो कोन लगाकर गेंदबाजी करते दिखे, जिनमें एक ऑफ स्टिक और दूसरा लेग स्टिक पर रखा गया था। इसी रणनीति से सलमान अली आगा और आर्यन दत्त ने अभिषेक के खिलाफ सफलता हासिल की थी।सूर्यकुमार ने कहा, ''चाहे ऑफ स्पिनर हो या बायें हाथ का स्पिनर, हमने काफी क्रिकेट खेली है और सभी तैयार हैं। हम फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें स्पिनर नई गेंद से भी बायें हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हैं। हमें अपनी रणनीति का पूरा ज्ञान है।''सुपर आठ में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा और सूर्यकुमार का फोकस टीम की रणनीति और अभिषेक की क्षमता पर बना हुआ है।

पंजाबी शादी में नोटों की बारिश का सच आया सामने

शादी में दूल्हन पर उड़ाए 8 करोड़?

सोशल मीडिया पर एक पंजाबी शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दूल्हे ने दुल्हन पर 8 करोड़ रुपये न्योछावर कर दिए. हालांकि, दूल्हे के भाई सिकंदर सिंह और इवेंट मैनेजर ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.



इन दिनों वायरल हो रहे पंजाबी शादी का वीडियो देख हर कोई हैरान रह गया है. (Photo: ITG)

शादियों में पैसा उड़ाना बेहद आम बात है. लेकिन आप सोचिए अगर किसी ने अपनी शादी में 8 करोड़ रुपये से कैश उड़ा दिया हो तो... जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों पंजाबी शादी का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें कपल के ऊपर नोटों की बारिश की जा रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि दुल्हे ने दुल्हन पर करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश उड़ा दिए हैं. लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है आइए जानते हैं... इसी बीच कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च किए गए, जिससे यह आयोजन कई लोगों के अनुसार कैश पार्टी में बदल गया. हालांकि, दूल्हे के भाई सिकंदर सिंह ने साफ किया है कि शादी के दौरान पैसों की बारिश तो हुई, लेकिन ऑनलाइन हो रहे दावों का आसपास नहीं. उन्होंने बताया कि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में ट्रक का कारोबार करता है. शादी 14 फरवरी को हुई थी. हमने जमकर पैसे लुटाए लेकिन खर्च लगभग 2 लाख रुपये ही हुए थे.सोशल मीडिया ने इसे करोड़ों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जो गलत है. कार्यक्रम का आयोजन करने वाले इवेंट मैनेजर और डीजे ने भी वायरल हो रहे 8 करोड़ रुपये के दावे को खारिज कर दिया. ⊙



जेईई में 'जीत' की बेठे से ज्यादा पैरेंट्स को खुशी

JEE मेंस-2026 सेशन- 1 का रिजल्ट आने के बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अर्नव गौतम, जिन्होंने JEE मेंस 2026 सेशन-1 में 100 पर्सेंटाइल हासिल किया, अपने माता-पिता के साथ रिजल्ट की खुशी में डांस करते नजर आ रहे हैं. यह खुशी का पल था, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि बड़ी सफलता के पीछे कितनी मेहनत और मानसिक दबाव छिपा होता है. ⊙

लोग बोले- 'डोगेश भाई' ने लूट ली महफिल

IIT बॉम्बे के लेक्चर हॉल में कुत्ते की एंट्री

IIT Bombay जैसे देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थान में जहां हर दिन पढ़ाई और लेक्चर की गंभीर माहौल होता है, वहीं एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी. एक 'चार पैरों वाला नया छात्र' अचानक लेक्चर हॉल में पहुंच गया और देखते ही देखते सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कुत्ता क्लासरूम की टेबल पर बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा नजर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे वह लेक्चर देने आया हो, न कि उसे सुनने. छात्रों ने भी उसे भगाने की बजाय हंसते हुए इस मजेदार पल का आनंद लिया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पीयूष



जायसवाल नाम के यूजर ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Finally Dogesh bhai got a table at IIT Bombay." सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार कमेंट किए. एक ने लिखा- Dogesh bhai ने तो मुझसे पहले IIT निकाल लिया. ⊙

OpenAI की कर्मचारी बोली- शादी से पहले साइन करो 'Prenup'

2 करोड़ की सैलरी पर शादी के लिए रखी शर्त

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की तेज रफ्तार ग्रोथ ने सिर्फ जॉब का बाजार नहीं बदला है, बल्कि युवाओं की सोच,खासतौर पर पैसे और रिश्तों को लेकर भी बदल दी है.

इसी बदलती सोच की मिसाल हैं गुजरि सिंह, जो OpenAi में काम करती हैं और शादी से पहले एक साफ शर्त रखती हैं-प्रेनप्चुअल एग्रीमेंट (प्रेनप) साइन करना जरूरी होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, 31 साल की गुजरि सिंह OpenAi की सेल्स टीम में कार्यरत हैं. उनकी सालाना सैलरी 2 लाख से 3 लाख अमेरिकी डॉलर के बीच बताई गई है, जो इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है. सिर्फ सैलरी ही नहीं, उनके पास कंपनी की इक्विटी भी है, जिससे भविष्य में



उनकी कुल संपत्ति और तेजी से बढ़ सकती है.

द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सिंह ने साफ कहा कि प्रेनप्चुअल एग्रीमेंट उनके लिए 'नॉन-नेगोशिएबल' है. उनका मानना है कि उनकी मौजूदा आय उनके करियर का शिखर नहीं है, बल्कि वे अभी अपने आर्थिक सफर की शुरुआत में हैं. ऐसे में वे अपने वर्तमान और भविष्य के एसेट्स की सुरक्षा को बेहद जरूरी मानती हैं. उनके अनुसार, यह फैसला अविश्वास से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता से जुड़ा है. प्रेनप एग्रीमेंट दरअसल, एक कानूनी समझौता होता है, जिसे शादी से पहले होने वाले पति-पत्नी आपसी सहमति से साइन करते हैं. ⊙

47 साल बाद साथ दिखेंगे रजनीकांत और कमल हासन

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में नई फिल्म का ऐलान



तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। साउथ सिनेमा के दो महान सुपरस्टार — रजनीकांत और कमल हासन — करीब 47 साल बाद एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का निर्देशन लोकप्रिय निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा एक खास प्रोमो वीडियो के जरिए की गई, जिसके सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।रजनीकांत, जिन्हें उनके प्रशंसक 'थलाइवर' के नाम से पुकारते हैं, और कमल हासन, जिन्हें 'उलगनायगन' कहा जाता है, दशकों से तमिल सिनेमा के स्तंभ माने जाते हैं। दोनों कलाकारों ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक दोनों अलग-अलग परियोजनाओं में व्यस्त रहे। अब लगभग पांच दशक बाद इन दोनों दिग्गजों का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है।घोषणा वीडियो में फिल्म की कहानी या किरदारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्रोमो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यह एक मेगा बजट प्रोजेक्ट होगा, जिसमें शानदार एक्शन, दमदार कहानी और भव्य प्रस्तुति देखने को मिल सकती है।फिल्म का शीर्षक और रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, फिर भी सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से ट्रेंड कर रही है। दर्शक इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फिल्म समीक्षकों के अनुसार रजनीकांत और कमल हासन का साथ आना न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर डालेगा, बल्कि तमिल सिनेमा के इतिहास में एक यादगार अध्याय भी जोड़ सकता है।



होमगार्ड भर्ती में विशेष प्राथमिकता

युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा का नया रास्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 हजार होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता देने की घोषणा की। प्रशिक्षित युवाओं को मानदेय, इमरजेंसी किट और 5 लाख रुपये का जीवन-चिकित्सा बीमा भी मिलेगा।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने का एक नया और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में होने वाली 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती में 'आपदा मित्रों' को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय न केवल आपदा प्रबंधन को और अधिक सशक्त बनाएगा, बल्कि सेवा भाव रखने वाले युवाओं को सरकारी तंत्र से जुड़ने का स्थायी अवसर भी देगा।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में आपदा मित्र के रूप में कार्य करना एक स्वैच्छिक सेवा है, जिसके लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। लेकिन अब, जब इन प्रशिक्षित आपदा मित्रों को होमगार्ड के रूप में भर्ती किया जाएगा, तो उन्हें सरकार की ओर से नियमित मानदेय (Honorarium) भी प्रदान किया जाएगा। इससे हजारों ऐसे युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा जो आपदा के समय समाज की मदद करने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी आपदा के समय सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाला व्यक्ति अक्सर एक आपदा मित्र ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 19 हजार आपदा मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड जैसे युवाओं के संगठनों से जुड़े लगभग 29,772 युवाओं को भी आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए हैं।इन युवाओं को आपदा के दौरान तत्काल मदद के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट भी प्रदान की गई है। इस किट में लाइफ जैकेट, फर्स्ट-एड बॉक्स, सुरक्षा उपकरण और अन्य 15 आवश्यक सामान शामिल हैं, जो उन्हें संकट की स्थिति में तत्परता से काम करने में सक्षम बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है।मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा मित्रों को तीन वर्ष के लिए 5 लाख रुपये का जीवन और चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस बीमा का संचालन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता (MoU) कर सुनिश्चित किया है। यह बीमा कवर उन युवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जो ड्यूटी के दौरान किसी भी अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में मदद की आवश्यकता में होंगे।सीएम योगी ने कहा कि आपदा मित्रों का प्रशिक्षण और उनका सरकारी तंत्र से जुड़ना प्रदेश में आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा। यह न केवल युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर देगा बल्कि उन्हें समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर प्रेरित करेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं।इस पहल के तहत आपदा मित्रों को होमगार्ड भर्ती में विशेष प्राथमिकता मिलने के बाद हजारों प्रशिक्षित युवाओं का योगदान सरकारी सेवाओं में सीधे शामिल होगा। सरकार की यह नीति न केवल रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि प्रदेश में प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी।योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षा का एक समग्र अवसर साबित हो रही है। आपदा मित्रों को होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता देने से प्रदेश में आपदा प्रबंधन और युवाओं की सामाजिक भागीदारी दोनों ही क्षेत्रों में नए मानक स्थापित होंगे।

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली में प्रदेश की बेटियों ने दिखाई दमखम

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में 18 और 19 फरवरी को आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में कई प्रदेशों की बेटियों ने भाग लेकर अपने जज्बे और तैयारी का परिचय दिया। रैली में दौड़ते समय तीन लड़कियां बेहोश भी हो गईं। लॉन्ग जंप में प्रतिभागियों को तीन मौके दिए गए, जिसमें किसी ने पहली, किसी ने तीसरी छलांग में 10 फीट की दूरी पार कर क्वालिफाई किया।करीब 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर इन बेटियों ने लखनऊ में पहुंचकर अपने सपनों को सच करने का प्रयास किया। वाराणसी की साक्षी यादव के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि पिछले साल फॉर्म भरा, लिखित परीक्षा दी, लेकिन लॉन्ग जंप में दो बार फेल होने के बाद उनके बड़े पापा ने हौसला बढ़ाया। तीसरे प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की, जिससे न केवल प्रतियोगिता बल्कि खुद पर भरोसा भी मजबूत हुआ।मथुरा की पूनम चौधरी के लिए सेना केवल करियर नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा है। उनके पिता और बड़े भाई दोनों सेना में हैं। पूनम ने 13 राज्यों में मेडल जीतकर, 400 मीटर दौड़ में नेशनल सिल्वर अचीवर और हॉर्स राइडिंग में नेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त कर अपनी तैयारी और जज्बे का प्रदर्शन किया।उत्तराखंड की रिया रावत इस भर्ती में अपने परिवार की पहली फौजी बनेंगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार का पहले सेना से कोई नाता नहीं था, लेकिन वे इस अवसर को गर्व और जिम्मेदारी दोनों मानती हैं। आगरा की निधि चौहान और अल्मोड़ा की ममता बिष्ट भी अपने परिवारों की प्रेरणा और अनुशासन के दम पर इस रैली में शामिल हुईं। निधि ने कहा कि पिताजी का भरोसा उन्हें हर दिन मैदान तक खींचकर लाता है, जबकि ममता ने पिता के सपनों को पूरा करना अपनी प्राथमिकता बताया। इस तरह, अग्निवीर रैली में बेटियों ने न केवल अपने साहस और क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अब महिला सैनिकों का भविष्य भी उज्ज्वल और प्रेरक है।

लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई: 40 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

टीवी भारतवर्ष लखनऊ



उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को एलडीए ने लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही आठ अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गोसाईगंज, सैरपुर और काकोरी क्षेत्रों में की गई। इसके साथ ही हजरतगंज के डालीबाग इलाके में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि गोसाईगंज के ग्राम कासिमपुर बिरूहा में चांद सराय क्रॉसिंग के पास लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यह प्लाटिंग बिना ले-आउट स्वीकृति के की जा रही थी। मौके पर एलडीए की टीम ने पहुंचकर इस अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इस अवैध प्लाटिंग में राजेन्द्र श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों का हाथ था। इसी दौरान प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि काकोरी के ग्राम इब्राहिमगंज, खुदाईट और पलेंहदा में भी अभियान चलाया गया। यहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। सोनू कनौजिया, छोटू, पप्पू लोधी, सोनू और प्रमोद यादव द्वारा कराई जा रही यह अवैध प्लाटिंग एलडीए ने ध्वस्त कर दी और जमीन को समतल करा दिया। प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी राजीव कुमार ने कहा कि सैरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी, बौरूमऊ और कोडरी भौली में भी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां दीपू यादव, राजेश वर्मा, स्वरूप समेत अन्य के द्वारा लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। एलडीए ने यहां तीन अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी। इसके अलावा हजरतगंज के डालीबाग क्षेत्र में प्रवर्तन जोन-6 के प्रभाकर सिंह ने बताया कि अंकित शर्मा और अन्य द्वारा बटलर रोड पर लगभग 300 वर्गमीटर भूखंड पर तीन मंजिला अवैध व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। विहित न्यायालय के आदेश के तहत इसे सील कर दिया गया। एलडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृत ले-आउट के कोई भी प्लाटिंग या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में सड़क पर उतरे सवर्ण मोर्चा के लोग, पुलिस से झड़प

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

शनिवार को लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में सवर्ण मोर्चा के लोगों ने अचानक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उनके हाथ में तिरंगा भी था। विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया।इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कुछ नाराज प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें बस में ठूसकर ईको गार्डन में छोड़ दिया।प्रदर्शनकारी परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा की ओर जा रहे थे, लेकिन केडी बाबू स्टेडियम के पास पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया।यातायात बाधित होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि भविष्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है।



यूपी बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर प्रशासन ने 19 मजिस्ट्रेटों के वेतन रोके

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपनी निर्धारित ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए।जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीर मामला माना और सभी 19 मजिस्ट्रेटों के वेतन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोकने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह छात्रों के हित और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधे असर डालता है।प्रशासन ने संबंधित मजिस्ट्रेटों को नोटिस भेजकर उनके जवाब मांगे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा ड्यूटी में उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रत्येक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है और भविष्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से देखा जाएगा।इस कदम से साफ संदेश गया है कि सरकारी ड्यूटी के प्रति उदासीनता और लापरवाही पर प्रशासन चुप नहीं बैठेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

लखनऊ नगर निगम में भाजपा-कांग्रेस

पार्षदों के बीच सदन शुरू होते ही बहस और तनातनी



लखनऊ नगर निगम का नवीनतम सत्र शुरू होते ही सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस और तनातनी देखने को मिली। मेयर सुषमा खर्कवाल ने इस सत्र को बुलाया था। हालांकि, सदन में कोई स्पष्ट विषय या एजेंडा नहीं होने के कारण विपक्ष और शासन पक्ष के पार्षद आमने-सामने आ गए।सूत्रों के अनुसार, भाजपा पार्षद के बोलने पर कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि उन्हें बार-बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस टिप्पणी के बाद दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अन्य पार्षदों को बीच में आकर मामला शांत करना पड़ा।दरअसल, कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने सदन में एजेंडा न होने पर विरोध जताया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद अन्नू मिश्रा बार-बार बोल रहे हैं और इसे रोकना चाहिए। इस बात ने दोनों पक्षों के बीच बहस को और हवा दे दी।इसके बाद, कांग्रेस पार्षद ममता रावत ने अन्नू मिश्रा के पास जाकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। उनका प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सदन में स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए और शांति बनाए रखी जा सके।नगर निगम सूत्रों ने बताया कि सदन में एजेंडा न होने और पार्षदों की सक्रियता के कारण यह टकराव हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की बहस आम है, लेकिन इसे सदन की कार्यवाही पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए।इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि लखनऊ नगर निगम के सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मतभेद कभी-कभी भावनात्मक बहस और तनातनी में बदल सकते हैं। हालांकि, अन्य पार्षदों और अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित रही और सदन की बैठक जारी रही।

उन्नाव पुलिस ने होली पर्व की सुरक्षा को लेकर किया सघन निरीक्षण

CO-SHO ने पैदल भ्रमण किया, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील



टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव। जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस क्रम में शनिवार को सीओ सिटी विनी सिंह और इंस्पेक्टर कोतवाली सी.के. मिश्र ने पुलिस बल के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों की पहचान की और वहां आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

सदर कोतवाली क्षेत्र के बाजारों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पहले विवादित रहे स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने कहा कि इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए होली के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थानों पर पीएसी और मोबाइल पुलिस टीमों की विशेष गश्त रहेगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों, व्यापारियों और संभ्रांत नागरिकों से भी बातचीत की और उन्हें त्योहार के दौरान संभावित समस्याओं और सुरक्षा संबंधी सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया। सीओ विनी सिंह ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा, "आपकी सतर्कता ही हमें सही समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगी। पुलिस के साथ सहयोग और जागरूकता से ही होली का त्योहार सुरक्षित और आनंदमय तरीके से मनाया जा सकता है।" इंस्पेक्टर सी.के. मिश्र ने बताया कि क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ा दी गई है और शराब की दुकानों, रंग-गुलाल की अस्थायी दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि हुड़दंग करने वालों या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। "हम चाहते हैं कि लोग आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ होली मनाएं। किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी," उन्होंने कहा। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का भी जायजा लिया। जहां कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वहां उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम या अन्य अव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो। इस दौरान अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर होली से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि होली के दिन शहर के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगी। इसके अलावा, नागरिकों और व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आस-पास के इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सीओ विनी सिंह और इंस्पेक्टर सी.के. मिश्र ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि लोगों के त्योहार को सुरक्षित और खुशीपूर्वक मनाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी पुलिस कर्मी पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उन्नाव पुलिस ने होली पर्व की सुरक्षा के लिए पैदल गश्त, संवेदनशील स्थलों की पहचान, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना, सीसीटीवी निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और यातायात व्यवस्थाओं की योजना तैयार कर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि नागरिक सतर्क रहें और पुलिस के सहयोग से होली को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं।

गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में लापरवाही: छह फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, एक महिला घायल



टीवी भारतवर्ष उन्नाव

जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। शुक्रवार रात मियागंज-सफीपुर मार्ग पर गांव मवई ब्रम्हनान के पास निर्माणाधीन अंडरपास के लिए खोदे गए करीब छह फीट गहरे गड्ढे में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के चार लोग बाल-बाल बच गए, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।जानकारी के अनुसार थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के कस्बा ऊगू निवासी विप्लव शुक्रवार रात अपने परिवार के साथ हसनगंज के गांव मवई से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार मवई ब्रम्हनान के पास पहुंची, अंधेरे के कारण सड़क पर खोदा गया गहरा गड्ढा दिखाई नहीं दिया और कार सीधे उसमें जा गिरी। कार गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला।हादसे में विप्लव की पत्नी रिया (30) को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान पैर की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि की। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार में सवार अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं।पीड़ित विप्लव ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था, वहां कोई चेतावनी संकेतक या बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने से राहगीरों को खतरा बना हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।



उन्नाव में पुलिस प्रशिक्षण का निरीक्षण: अपर पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट आरक्षियों की तैयारी और अनुशासन की समीक्षा

टीवी भारतवर्ष वाराणसी

पुलिस प्रशिक्षण की गुणवत्ता और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (अपर एसपी) उत्तरी, अखिलेश सिंह ने दोस्ती नगर स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की इनडोर और आउटडोर गतिविधियों का विस्तार से अवलोकन किया और उनकी तैयारी की समीक्षा की। अपर एसपी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनके सामने आने वाली समस्याओं को समझा और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण के हर चरण में पारदर्शिता, गंभीरता और कड़ाई बरती जाए, ताकि भावी आरक्षी न केवल प्रशिक्षित बल्कि अनुशासित और सक्षम बनें। निरीक्षण के दौरान आउटडोर गतिविधियों के तहत रिक्रूट सिपाहियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया गया। इसमें लंबी छलांग, दौड़ और अन्य शारीरिक अभ्यास शामिल थे। अपर एसपी ने स्वयं मैदान में उपस्थित होकर लंबी छलांग का अभ्यास कराया और प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में शारीरिक फिटनेस अत्यंत आवश्यक है और नियमित अभ्यास से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अधिकारी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हों। अपर एसपी ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी अनुशासनहीनता या अनुपस्थिति की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमित मार्गदर्शन और परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं। अपर एसपी अखिलेश सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा, "एक प्रशिक्षित और सक्षम पुलिस बल ही कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। आप सभी को अपने प्रशिक्षण में पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना के साथ योगदान देना होगा। यही आपके भविष्य की सफलता और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।" उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह पुलिस बल के कार्यक्षमता और जनता की सुरक्षा की नींव है। उन्होंने अधिकारियों और प्रशिक्षुओं से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहें। इस अवसर पर फायर ट्रेनिंग सेंटर के सभी प्रशिक्षक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपायों और सुविधाओं की भी समीक्षा की। अपर एसपी ने अधिकारियों से कहा कि प्रशिक्षण केंद्र में किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी अंत में अपर एसपी ने सभी प्रशिक्षुओं को संदेश दिया कि पुलिस बल की प्रतिष्ठा और समाज की सुरक्षा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ प्रशिक्षण पूरा करने और भविष्य में उत्कृष्ट सेवा देने की प्रेरणा दी। इस निरीक्षण के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्नाव में प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता के साथ-साथ प्रशिक्षुओं की मानसिक और व्यावहारिक तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।



अंपायर मानिक की पत्नी बोलीं- KCA मदद करे

टीवी भारतवर्ष कानपुर

राज्य क्रिकेट संघ (KCA) से जुड़े वरिष्ठ अंपायर और क्रिकेट प्रेमी मानिक गुप्ता का निधन मधुमक्खियों के काटने से हो गया। उनके अचानक निधन ने पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया है। मानिक गुप्ता के परिवार में पत्नी कुसुमलता और चार बेटियां हैं। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी समृद्धि अभी 18 साल की है और B.Sc कर रही है। कुसुमलता ने बताया कि मानिक हमेशा अपनी छोटी बेटी को सरकारी नौकरी करते देखना चाहते थे। परिवार की आर्थिक और भावनात्मक स्थिति को लेकर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है।कुसुमलता ने बताया, "अब यह दिन देखना था कि मेरी बेटी ने बेटे का फर्ज निभाया। हमारे घर का सहारा, मानिक ही थे। उनकी कमाई से ही घर चलता था। अब मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वह जब 19 साल के थे तभी से KCA में जुड़े थे। पहले खेलते थे, फिर अंपायरिंग करते थे। यही उनके परिवार का आधार था। अब मैं बस यही चाहती हूं कि हमारी मदद की जाए ताकि मेरी बेटी अपने सपने पूरे कर सके।"बड़ी बेटी प्रियंका ने भी परिवार की मुश्किलें साझा कीं। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमें आर्थिक मदद मिले। अब घर में केवल मेरी छोटी बहन और मां हैं। KCA और UPCA यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मदद मिलनी चाहिए। अगर समय पर सही इलाज मिलता तो शायद पापा बच जाते। अब हमारी बहन और मां का कोई सहारा नहीं बचा।"मानिक गुप्ता को अस्पताल ले जाने वाले राहुल सप्रु ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि मानिक को मधुमक्खियों ने काटा है, वह तुरंत पहुंचे और अपनी गाड़ी से उन्हें शुक्लागंज के दो अस्पतालों में ले गए। वहां बताया गया कि एंटी डोज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद उन्हें सीधे हैलट अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।राहुल सप्रु ने कहा, "हमने मदद के लिए KCA के अधिकारियों को सूचित किया। सभी अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे। हम लोग उनके परिवार के लिए कुछ जरूर करेंगे। मैंने प्रस्ताव रखा है कि एक श्रद्धांजलि मैच आयोजित किया जाए। जो भी राशि एकत्र होगी, उसके साथ ही सहयोग की राशि उनके परिवार को दी जाएगी। इस राशि से उनकी छोटी बेटी की पढ़ाई और भविष्य की शादी में मदद की जाएगी।"मानिक गुप्ता का क्रिकेट में योगदान और उनके परिवार के लिए उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन ने न केवल परिवार को बल्कि क्रिकेट समुदाय को भी स्तब्ध कर दिया है। परिवार ने KCA और UPCA से तत्काल सहायता की अपील की है, ताकि उनकी छोटी बेटी समृद्धि अपने सपनों को पूरा कर सके।क्रिकेट जगत के लोग भी इस हादसे से स्तब्ध हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के दुखद घटनाओं में खिलाड़ियों और उनके परिवार की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आगामी सप्ताह में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि मैच से एकत्र राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की पढ़ाई में किया जाएगा।

सरकारी गेहूं खरीद अभियान की तैयारी, 87 क्रय केंद्र होंगे सक्रिय

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के गेहूं की खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में 87 सरकारी क्रय केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है, जहां से 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2589 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले साल यह 2425 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपये अधिक मिलेगा। सरकारी खरीद की जिम्मेदारी विपणन शाखा, पीसीएफ और एफसीआई को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने इन केंद्रों को खोलने और संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। अब तक 62 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष यादव ने बताया कि किसानों को सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने से पहले विभागीय पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया के लिए किसानों को अपना बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। संतोष यादव ने किसानों को सलाह दी कि पंजीकरण के समय खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही जानकारी भरें। ऐसा करने से भुगतान में आसानी होगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर समय-समय पर सूचना प्राप्त होगी। सरकारी खरीद प्रक्रिया से किसानों को लाभ मिलेगा और उन्हें सुरक्षित तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार किसानों को उचित मूल्य देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी पूरा कर रही है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समय पर पंजीकरण कराएं, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके और उन्हें उनके गेहूं का सही मूल्य मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत राहत वितरित की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3,500 परिवारों को 175 करोड़ रुपये वितरित किए। साथ ही आपदा प्रबंधन, स्मार्ट कृषि इकाई और मौसम पूर्वानुमान केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया।



टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3,500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज और भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का भी शिलान्यास किया गया।सीएम योगी ने किसानों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अन्नदाता किसान उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट हाल ही में पारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए अनेक योजनाएं पास कराई गई हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट के अंतर्गत लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि एक बटन दबाते ही आज 460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में लाभार्थी परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2.51 लाख किसान परिवारों को मिली 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों को सूखे और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के समय संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के जरिए किसान अपनी फसल की हानि के बावजूद आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि पहले केवल किसान कवर होता था, जबकि परिवार के सदस्य, बटाईदार और सह किसान इसमें शामिल नहीं होते थे। हमारी सरकार में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के तहत किसान या उनके परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री ने बताया कि आज आपदा प्रभावित 3,500 पीड़ित किसानों, सह किसानों, पारिवारिक सदस्यों और बटाईदारों को लाभान्वित किया गया। इससे पहले 16 जून 2025 को 11,690 किसानों और आश्रितों को 561.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कल तक यह राशि सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाए।आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी आपदा मित्रों की भूमिका पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत स्काउट एंड गाइड) को प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें सात दिवसीय प्रशिक्षण के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में लाइफ जैकेट, सर्च टॉर्च, फर्स्ट-एड बॉक्स, सेफ्टी हेलमेट और अन्य 15 आवश्यक आइटम शामिल हैं। इन स्वयंसेवकों का तीन वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा भी सुनिश्चित किया गया है।सीएम ने कहा कि पहले आपदा आने पर पीड़ितों को राहत मिलने में वर्षों लग जाते थे। 2015-16 में केवल कुछ रुपये ही किसान के खाते में आए थे। ।सीएम ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी और आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर राडार की स्थापना की जाएगी, जिससे मौसम का पूर्वानुमान और आकाशीय बिजली गिरने के खतरे की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2,000 ब्लॉक स्तर के ऑटोमेटिक रेन गेज लगभग पूर्ण हो चुके हैं।इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, उप्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, प्रमुख सचिव (कृषि) रवींद्र कुमार और प्रमुख सचिव (राजस्व) अपर्णा यू मौजूद रहे।

धागा कारोबारी से 20 लाख की वसूली: मेरठ में दो दरोगा गिरफ्तार एनकाउंटर की दी थी धमकी

टीवी भारतवर्ष मेरठ

धागा कारोबारी से 20 लाख रुपये की कथित वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दरोगाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पहले लोहियानगर थाना में तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली।मामला तब सामने आया जब टीपीनगर थाना क्षेत्र निवासी रासिक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे से शिकायत की। रासिक ने आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और एनकाउंटर करने की धमकी दी। भय के कारण उसने 20 लाख रुपये दे दिए।एसएसपी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गईं। हालांकि एफआईआर दर्ज होते ही दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।लगातार दबिश के बाद पुलिस ने दोनों दरोगाओं को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्दी की आड़ में अवैध वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

प्रयागराज में शंकराचार्य और शिष्य के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

टीवी भारतवर्ष वाराणसी



उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बलात्कार एवं यौन शोषण विरोधी विशेष न्यायालय ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सहायक न्यायाधीश विनोद कुमार चौरासिया ने पुलिस की पूर्व निष्क्रियता पर असंतोष जताते हुए झूंसी थाने को तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। माघ मेले के दौरान आरोप सामने आने के बाद से यह मामला क्षेत्र में व्यापक चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। यह प्रकरण श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा 28 जनवरी को दायर याचिका से शुरू हुआ। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि वाराणसी के विद्यामठ स्थित आश्रम में 'गुरु सेवा' के नाम पर नाबालिग बच्चों का सुनियोजित यौन शोषण किया गया। याचिकाकर्ता ने एक सीडी को सबूत के रूप में पेश करते हुए दावा किया कि लगभग 20 पीड़ित बच्चों ने उनसे संपर्क किया और धार्मिक आड़ में शोषण के एक पैटर्न का खुलासा किया।13 फरवरी को अदालत ने दो नाबालिग पीड़ितों के वीडियो रिकॉर्डेड बयान दर्ज किए। पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर न्यायाधीश ने इन बयानों की समीक्षा की और आदेश सुरक्षित रखने के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। यह कदम बाल संरक्षण कानूनों, विशेषकर पॉक्सो अधिनियम, के तहत न्यायिक सक्रियता का संकेत माना जा रहा है। एक चर्चित धार्मिक व्यक्तित्व के विरुद्ध इस प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप क्षेत्र में कानूनी और सामाजिक बहस को और तेज कर सकता है।

एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अर्द्धनग्न प्रदर्शन पर मायावती ने जताई नाराजगी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ



बहुजन समाज पार्टी (BSP) की नेता मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान हुए अर्द्धनग्न प्रदर्शन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इसे "अति-अशोभनीय और निन्दनीय" करार दिया। अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा कि इस सम्मेलन में देश और विदेश के कई प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था और यह इवेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। ऐसे में किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन आचरण देश की छवि और गरिमा को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा, "अगर यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किन्तु इस स्तर पर होने के बावजूद ऐसी हरकत करना चिंताजनक है। यह जरूरी है कि हम अपने देश की प्रतिष्ठा और इमेज को बनाए रखें।" मायावती ने विशेष रूप से उन व्यक्तियों की आलोचना की, जिन्होंने अर्द्धनग्न होकर अपना विरोध या रोष प्रकट किया। उनका कहना था कि इन लोगों में अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस तरह का प्रदर्शन न केवल अशोभनीय है, बल्कि सार्वजनिक और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी धूमिल करता है। नेता ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह अपनी राय व्यक्त करे, लेकिन यह भी जरूरी है कि ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे देश की गरिमा को ठेस न पहुंचे। उन्होंने सभी से यह अपील की कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का सम्मान बनाए रखना सभी का कर्तव्य है और अनुशासनहीन व्यवहार को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एआई और तकनीकी विकास के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह समिट आयोजित किया गया था, और इस दौरान हुए विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दिया है। उनके इस स्पष्ट बयान से यह संदेश गया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनुशासन और गरिमा बनाए रखना आवश्यक है।

